



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 चैत्र 1940 (श10)  
(सं0 पटना 269) पटना, सोमवार 26 मार्च 2018

---

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना  
23 मार्च 2018

सं0 10/मु. नियमावली-05/2018-1060—न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम सं0 VII, सन् 1870) की धारा-27 और धारा 34 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा राज्य के न्यायालयों एवं कार्यालयों में ई-कोर्ट फीस के द्वारा फीस के भुगतान के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: —

#### बिहार ई-कोर्ट फीस (एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली, 2018

##### अध्याय-1

##### विस्तार और प्रारम्भ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। —(1) यह नियमावली “बिहार ई-कोर्ट फीस (एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली, 2018” कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

(4) विभागीय अधिसूचना सं0 2039 दिनांक 02.05.2017 द्वारा नियुक्त एजेन्सी एवं तत्संबंधी किए गए एकरारनामा के अनुशरण में भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ: — (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में: —

(i) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या- VII सन् 1870) से है;

(ii) “करार” से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकार एवं केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण/सरकार द्वारा चयनित एजेन्सी के मध्य निष्पादित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति की शर्तों का वर्णन करने वाले करार से है;

(iii) “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है सरकार अथवा निबंधन महानिरीक्षक से है, जिसे इस नियमावली के अधीन समस्त अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

- (iv) “अनुमोदित मध्यवर्तियों” से अभिप्रेत है केन्द्रीय अनुरक्षण अभिकरण एवं सभी कार्यालयों एवं संस्थाओं सहित प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों से है, जो इस नियमावली के अधीन, न्यायालय फीस के संग्रह के लिए सरकार तथा न्यायालय फीस दाता के मध्य किसी मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेतु सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त हो;
- (v) “प्राधिकृत संग्रह केन्द्र” से अभिप्रेत है ऐसे अभिकर्ता से है, जिसे न्यायालय फीस के संग्रह के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण एवं न्यायालय फीस दाता के मध्य मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेतु सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण द्वारा नियुक्त किया गया हो;
- (vi) “केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण” से अभिप्रेत है ऐसे अभिकरण से है, जिसे राज्य में अथवा ऐसे स्थानों में, जैसा कि सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किया जाये, न्यायालय फीस प्रशासन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्त किया गया हो;
- (vii) “विभाग” से अभिप्रेत है मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार;
- (viii) “प्रपत्र” से अभिप्रेत है समय-समय पर नियुक्ति प्राधिकारी/रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र;
- (ix) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (बिहार राज्य में लागू होने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित) में उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

## अध्याय-2

### केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति

3. केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त, कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्था, भारतीय अनुसूचित बैंक या कम्पनी, जो निक्षेप सेवाओं को उपलब्ध कराने में संलग्न हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कम्पनी चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप के लिए योग्य होंगे।

4. नियुक्ति प्राधिकारी राज्य के विनिर्दिष्ट न्यायालयों में जैसा कि उसके द्वारा समय-समय पर घोषित किया जाये, न्यायालय फीस प्रशासन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के क्रियान्वयन हेतु राज्य के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में कार्य करने हेतु अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में एक समुचित अभिकरण का चयन एवं नियुक्ति करेगा:-

- (1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण से संबंधित, समय-समय पर निर्गत केन्द्र सरकार की संस्तुतियाँ, यदि कोई हो, के आधार पर;
- (2) सम्यक् रूप से गठित विशेषज्ञ चयन समिति के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित करके;
- 5. इस नियमावली के अधीन नियुक्त केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की अवधि 05 वर्ष होगी।
- 6. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी तथा अभिकरण, नियुक्ति प्राधिकार के साथ करार करेगा।
- (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण उप नियम (1) में निर्दिष्ट करार के साथ नियुक्ति प्राधिकार के पक्ष में दायित्व, क्षतिपूर्ति का बन्ध-पत्र एवं बैंक गारन्टी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये, निष्पादित करेगा।
- 7. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति किसी बाध्यता या करार की शर्तों या इस नियमावली या अधिनियम के उपबंधों के भंग होने या वित्तीय अनियमितता या किसी अन्य पर्याप्त कारण, जो अभिलिखित किये जायेंगे, के आधार पर नियुक्ति, की तय की गयी शर्त की अवधि के पूर्व समाप्त की जा सकती है।
- (2) नियुक्ति को समाप्त करने का विनिश्चय: -
  - (i) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को उप नियम (1) के क्रम में लिये गये निर्णय से संबंधित आधारों के संबंध में कारण बताओं नोटिस देने के पश्चात।
  - (ii) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात।
  - (iii) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात, तथा,

- (iv) बाध्यता के भंग होने की स्थिति में केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा कारण बताओं नोटिस में उल्लिखित समयावधि के अंतर्गत भंग का निराकरण किये जाने में विफल होने की स्थिति में किया जायेगा।
- (3) यदि आधार, जिस पर नियुक्ति प्राधिकार ने नियुक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया है, ऐसा है जिससे राज्य के राजस्व की क्षति भी हुई है तो केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा आरोपित की जाय के अतिरिक्त राजस्व क्षति की सम्पूर्ण धनराशि का संदाय करने के लिए बाध्य होगा।
- (4) इस नियम के अधीन नियुक्ति की समाप्ति पर, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण नियुक्ति की अवधि में जनित समस्त डाटा सरकार को स्थानान्तरित कर देगा। केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण नियुक्ति के समाप्ति के पश्चात् नियुक्ति की अवधि में जनित डाटा को अपने व्यापार या किसी उद्देश्य हेतु चाहे जो भी हो, प्रयोग में न लाएगा और न लाने देगा।
8. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति के नवीकरण के लिए आवेदन नियुक्ति की चालू अवधि के समाप्ति के कम से कम तीन माह पूर्व नियुक्ति प्राधिकार को किया जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकार, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर विनिश्चय करने के पूर्व विभाग, केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण अथवा प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों अथवा किसी अन्य व्यक्ति या निकाय से कोई सूचना अथवा अभिलेख मंगा सकता है।
- (3) नवीकरण के औचित्य का समाधान हो जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति का नवीकरण कर सकता है।
- (4) यदि नियुक्ति प्राधिकार नियुक्ति का नवीकरण करने का विनिश्चय करता है तो नियम 6 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट एक नया करार तथा नियम 6 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट वचनबद्ध एवं क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र उपयुक्त संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ निष्पादित किया जायेगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकार को अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, नियुक्ति अवधि के नवीकरण से इन्कार करने की शक्ति होगी।

### अध्याय-3

#### केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के कर्तव्य

9. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण निम्नलिखित कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होगा:-
- (i) नियुक्ति प्राधिकार के परामर्श से अभिहित स्थानों पर आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधायें, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का निर्माण एवं मेल सर्वर से इसका संयोजन।
- (ii) अभिहित न्यायालयों एवं चिन्हित नगरों/स्थानों के अधिकृत संग्रह केन्द्रों (न्याय फीस के भुगतान हेतु सम्पर्क स्थान) में आवश्यकता आधारित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का निर्माण।
- (iii) विभाग/न्यायालय के कार्मिक को, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, उपकरणों के प्रयोग व संचालन के लिए उचित एवं पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (iv) न्यायालय फीस के संग्रह एवं ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों को निर्गत करने हेतु प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों के चयन में सहयोग प्रदान करना।
- (v) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण, प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों के केन्द्रीय सर्वर, न्यायालय और विभाग के पर्यवेक्षणीय एवं नियंत्रक अधिकारियों के कार्यालयों या अन्य किसी कार्यालय या न्यायालय और अन्य कार्यालय या स्थान जैसा कि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- (vi) इस नियमावली के अनुसार राज्य के न्यायालय फीस का संग्रह करना एवं जैसा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाय उसे उचित लेखा शीर्षक में प्रेषित करना।
- (vii) इस नियमावली के अधीन अपेक्षित विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट विकसित करना एवं उसकी रूप रेखा तैयार करना, जैसा समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

- (viii) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसा अपेक्षित अन्तरापृष्ठ विकसित करें जैसा नियुक्ति प्राधिकार केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और न्यायालय के बीच परस्पर सहमति बने।
- (ix) न्यायालय फीस नियमावली, उच्च न्यायालय नियमावली, पटना उच्च न्यायालय की व्यवहार न्यायालय नियमावली तथा दंड न्यायालय नियमावली में पटना उच्च न्यायालय द्वारा “कल्याण निधि स्टाम्प” के संबंध में, “ई-भुगतान” के माध्यम से फीस भुगतान करने हेतु, समय-समय पर, किए गए प्रावधानों का पालन करना।
- (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण राज्य में प्रारंभ किये ई-कोर्ट फीस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कोई अन्य तकनीक या विवरण नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना सम्यक् रूप से नियुक्त प्राधिकृत संग्रह केन्द्रों से भिन्न किसी अन्य को उपलब्ध, स्थानान्तरित या उसके साथ साझा नहीं करेगा।
10. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण संग्रहीत न्यायालय फीस की धनराशि पर एकरार में तय कमीशन पाने का हकदार होगा।
- (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को देय कमीशन नियम 19 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।
11. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण को इस प्रकार सॉफ्टवेयर का प्रयोग और रूपांकन करना होगा, जिससे कि ई-कोर्ट-फीस प्रमाण पत्र पर कम से कम निम्नवत् विवरण प्रदर्शित हो-
- (i) प्रमाण पत्र की विशिष्ट विलक्षण पहचान संख्या, जिससे कि ई-कोर्ट-फीस प्रणाली के अस्तित्व पर्यन्त किसी अन्य प्रमाण पत्र में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।
- (ii) निर्गम का दिनांक और समय।
- (iii) शब्दों और अंकों में प्रमाण पत्र के माध्यम से सतत न्यायालय फीस की धनराशि।
- (iv) ई-कोर्ट-फीस पहचान पत्र के रु. 99/- से अधिक होने की दशा में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले पक्षकार का नाम।
- (v) अनुमोदित मध्यवर्ती अथवा निर्गम शाखा का लोकेशन कोड।
- (vi) प्रमाण-पत्र का कोई अन्य विशिष्ट प्रतीक उदाहरणार्थ बार कोड आदि, यदि कोई हो।
- (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सॉफ्टवेयर में निम्न की भी व्यवस्था होगी-
- (i) न्यायालयों/पदाभिहित अधिकारियों को किसी दस्तावेज में प्रयुक्त ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र को लॉक करने की सुविधा।
- (ii) खराब, अप्रयुक्त अथवा प्रयोग के लिए अनपेक्षित ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की सुविधा।
- (iii) किसी ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र को तलाश करने उससे अभिगम स्थापित करने एवं उसका अवलोकन करने और प्रबंध सूचना प्रणाली पर अभिगम स्थापित करने के लिए न्यायालयों के पदाभिहित अधिकारियों द्वारा प्रयोग लिए जाने वाले आश्यक यूजर आईडी व पासवर्ड। केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण संबंधित पदाधिकारियों अथवा न्यायालयों को नियुक्ति प्राधिकार अथवा उच्च न्यायालय के महानिबंधक के निर्देशानुसार यह पासवर्ड उपलब्ध करायेगा।
- (iv) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई-कोर्ट फीस सर्वर पर निर्गत ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों के विवरण की उपलब्धता, और
- (v) ई-कोर्ट फीस संबंधित ऐसे विवरण एवं रिपोर्ट की केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की वेबसाइट पर उपलब्धता, जो उप नियम (2) के खण्ड (ग) में उल्लिखित अधिकारियों के लिए अभिगम्य होगा।

**अध्याय-4**  
**प्राधिकृत संग्रह केन्द्र**

12. केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण, नियुक्ति प्राधिकार के पूर्व के अनुमोदन से, न्यायालय फीस के संग्रह के लिए केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण एवं न्यायालय फीस दाता के मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेतु अभिकर्ता (अभिकर्ताओं), जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकृत संग्रह केंद्र कहा गया है, की नियुक्ति कर सकता है। प्राधिकृत संग्रह केंद्रों को देय सेवा फीस, कमीशन या फीस आदि का संदाय केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अपने स्तर से, जैसा कि उनके मध्य पारस्परिक करार हुआ, किया जायेगा।

13. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नियंत्रणाधीन कोई अनुसूचित बैंक, कोई वित्तीय संस्था, कोई उपक्रम अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्था, कोई उपक्रम या पोस्ट ऑफिस प्राधिकृत केंद्र के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (2) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर किसी व्यक्ति को अधिकृत संग्रह केंद्र के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।
- (3) किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की वेबसाइट पर पंजीकरण के उपरांत स्वयं अथवा किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का क्रय ऑनलाइन भी किया जा सकता है।

14. राज्य के विनिर्दिष्ट स्थानों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समय-समय पर घोषित किया गया हो, में केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण के समस्त कार्यालय/शाखायें भी न्यायालय फीस की धनराशि का संग्रह कर सकेगी, जिसके लिए नियम 12 के अधीन नियुक्ति प्राधिकार से पृथक रूप से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

15. समस्त ऐसे अनुमोदित मध्यवर्ती, अपेक्षित कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, इण्टरनेट संयोजन और अन्य संबंधित अवसंरचना से सुसज्जित होंगे, जो ई-कोर्ट फीस प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए, जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायें, आवश्यक है।

16. नियम 15 में निर्दिष्ट उपकरण एवं अवसंरचना को उपलब्ध कराये जाने की लागत, का वहन संबंधित अनुमोदित मध्यवर्तियों द्वारा किया जायेगा।

17. राज्य ई-कोर्ट फीस प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने हेतु विक्रय केन्द्रों की स्थापना हेतु न्यायालयों/स्थलों को निर्दिष्ट कर सकेगा।

18. नियुक्ति प्राधिकार किसी भी समय अभिलिखित कारणों से केन्द्रीय अभिलेखों-अनुरक्षण अभिकरण को किसी प्राधिकृत संग्रह केंद्र के अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण ऐसे परामर्श पर ऐसे प्राधिकृत संग्रह केंद्र अभिकरण को समाप्त करेगा।

**अध्याय-5**  
**सरकारी लेखा में न्यायालय फीस का प्रेषण**

19. (1) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण अपने कार्यालयों/शाखाओं और प्राधिकृत संग्रह केंद्र द्वारा संग्रहीत न्यायालय फीस की समेकित धनराशि का मिलान करेगा एवं उसे संग्रह करने की तिथि से अगले कार्य दिवस (T+1) की अवधि समाप्त होने से पूर्व अथवा अनुबन्ध पत्र में परस्पर सहमति से निर्धारित अवधि जो 02 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होगी, के अंदर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोर्ट फीस के उचित लेखाशीर्षक में जमा करेगा।

- (2) राज्य के उचित लेखा शीर्ष में न्यायालय फीस का प्रेषण केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लेयरिंग सिस्टम (ईसीएस), रियल टाइम ग्रास सेटलमेण्ट (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी), चालान या अन्यथा, जैसा समय-समय पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा लिखित रूप में निर्देशित किया जाये, के माध्यम से किया जायेगा।

- (3) इस नियम (1) में संदर्भित जमा धनराशि को "राजकोष में विनिर्दिष्ट लेखाशीर्ष के अंतर्गत संव्यहार करने हेतु अधिकृत बैंको में चालान के द्वारा जमा कर अथवा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समय-समय पर निदेशित प्रक्रिया के माध्यम से अंतरित किया जाय" सरकारी कोषागार या प्राधिकृत बैंक तथा केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण ऐसी जमा की गयी धनराशि का दैनिक खाता ऐसे प्रारूप में संरक्षित रखेंगे, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

- (4) केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण को उसके द्वारा प्रस्तुत समेकित प्राप्त विवरण के आधार पर मासिक अथवा पाक्षिक आधार पर, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये या करार के अनुसार कमीशन का भुगतान किया जायेगा। इस उप नियम के अधीन कमीशन का भुगतान स्ट्रोत पर आयकर कटौती के उपरांत किया जायेगा। केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण कोई अन्य कर जो केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन देय है के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

#### अध्याय-6

#### ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के निर्गमन की प्रक्रिया

20. न्यायालय फीस का सन्दाय करने के लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित न्यायालय में केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की प्राधिकृत संग्रह केन्द्र पर ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा।

21. न्यायालय फीस की धनराशि का सन्दाय नकद या पे-आर्डर या चेक या बैंक ड्रफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स समाशोधन प्रणाली या रियल टाईम ग्रास सेटलमेंट अथवा निधियों के अंतरण की अन्य विधि, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, द्वारा किया जायेगा।

22. (1) अनुमोदित मध्यवर्ती का प्राधिकृत पदाधिकारी नियम 21 के अधीन ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) अनुमोदित मध्यवर्ती, जिसके द्वारा ई-कोर्ट फीस प्रमाण जारी किया जा रहा है एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जिसमें प्रतिदिन उसके द्वारा जारी किये गये ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का खाता रखा जायेगा तथा ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के क्रेता या प्राधिकृत व्यक्ति, जैसा भी हो, के हस्ताक्षर रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ पर करायेगा।

23. अनुमोदित मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति जिसे ई-कोर्ट फीस प्रमाण जारी किये जाने का कार्य सौंपा गया है, उसके अभिकरण या संस्था का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है एवं यथोचित विश्वास का है।

24. ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का मुद्रण टिकाऊ कागज पर न धुलने वाली अमिट काली स्याही से अथवा जिस प्रकार नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो, किया जायेगा।

25. निर्गत ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का विवरण केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई-कोर्ट फीस वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा और इस निमित्त नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिसमें न्यायालय कर्मी शामिल हो, को सुलभ होगा जिनके पास केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा प्रदान किये जाने वाले वैध यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध हो।

26. ऐसा व्यक्ति जिसके पास ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र है एवं जिसके द्वारा अतिरिक्त न्यायालय फीस का भुगतान किया जाना है निर्धारित प्रारूप में अनुमोदित मध्यवर्ती के समक्ष उक्त अतिरिक्त न्यायालय फीस के भुगतान के साथ प्रार्थना पत्र दे सकता है।

27. (1) अनुमोदित मध्यवर्ती ऐसे अतिरिक्त न्यायालय फीस के संदाय हेतु नियम 20 से 24 तक में यथा विहित विधि से कागज के पृथक पत्र पर ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

(2) अधिनियम के अधीन दस्तावेज पर प्रभार्य न्यायालय फीस के भुगतान हेतु ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के साथ-साथ न्यायिक स्टाम्प का भी प्रयोग किया जा सकता है।

28. (1) किसी दस्तावेज में प्रयुक्त ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र का किसी दूसरे दस्तावेज में प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) का उल्लंघन करते हुये लिखा गया दस्तावेज अस्टाम्पित माना जायेगा और इस पर अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

29. दस्तावेज के ऊपर वाले भाग पर ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र की विलक्षण एवं विशिष्ट पहचान संख्या लिखी या मुद्रित की जायेगी।

30. न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित जाँच के उपरांत, केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण की सुसंगत वेबसाइट पर अभिगम स्थापित कर दस्तावेज में प्रयोग किये गये ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र की शुद्धता और प्रामाणिकता को विशिष्ट पहचान संख्या से अथवा बार-कोड स्कैनर की मदद से सत्यापित करेंगे। उक्त सत्यापन के उपरांत न्यायालयों द्वारा केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण द्वारा प्रदत्त यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र को लॉक किया जायेगा, जिससे कि इस प्रमाण पत्र का पुनः प्रयोग न हो सके।

केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण द्वारा प्रदत्त यूजर आईडी और पासवर्ड को संबंधित अधिकारी प्रकट नहीं करेगा तथा यूजर आईडी या पासवर्ड जो संबंधित अधिकारी को प्रदत्त है, के गलत और अनाधिकृत प्रयोग से सरकार को यदि कोई हानि होती है उसके लिये संबंधित अधिकारी उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

अध्याय-7  
ई-कोर्ट फीस की वापसी

31. (1) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870, बिहार स्टाम्प नियमावली, 1954 तथा न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के तहत बिहार सरकार द्वारा निर्मित नियमावली, यथा संशोधित के अधीन वापसी और छूट की प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित यथा आवश्यक उपांतर के साथ प्रभावी होगी।
- (2) खराब हुये या दुरुपयोग किये गये या अनपेक्षित ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों की वापसी या छूट के लिए ई-कोर्ट फीस निर्गमन के 6 माह के अंदर आवेदन पत्र ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र के साथ ऐसे समाहर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे जिसके क्षेत्राधिकार में ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र को न्यायालय द्वारा प्रयोग हेतु लॉक किया जाना अपेक्षित है।
- (3) समाहर्ता केंद्रीय, अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण एवं संबंधित न्यायालय के रजिस्ट्री से तथा संबंधित कोषागार से ई-कोर्ट फीस प्रमाण-पत्र को सत्यापित कराने के उपरांत सत्यापित किये गये ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र पर शब्द "निरस्त" अंकित करके अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ पृष्ठांकन करेगा।
- (4) समाहर्ता अपने कार्यालय में ऐसे निरस्त किये गये ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों का विवरण संरक्षित रखेगा।
- (5) केन्द्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा निर्गत ई-कोर्ट फीस प्रमाण-पत्र में कोई त्रुटि पायी जाती है तो जबतक सरकार के खाते में उससे संबंधित राशि का हस्तान्तरण नहीं हो जाता है, त्रुटि सुधार कर नया ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र निर्गत कर सकेंगे तथा इससे संबंधित विवरण संरक्षित रखेंगे। साथही उस तिथि के प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन में उसे सम्मिलित करेंगे।
- (6) उपर्युक्त उप नियम (3) के अन्तर्गत प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदनों से संतुष्ट होते हुए यदि यह स्थापित होता हो कि आवेदन में उपदर्शित ई-कोर्ट फीस की राशि आवेदक द्वारा जमा की गयी है, तो, जमा राशि की 10% (दस प्रतिशत) राशि, न्यूनतम 100/-रु. (एक सौ रूपए), अधिकतम रु. 5000/- (पांच हजार रूपए), की कटौती करते हुए राशि की वापसी की जाएगी।

भाग-8  
निरीक्षण, संपरीक्षा एवं प्रणाली के संपादन का मूल्यांकन

32. (1) निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी विभाग का कोई पर्यवेक्षणीय अधिकारी या नियुक्ति प्राधिकार या निबंधन महानिरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का तकनीकी एवं संपरीक्षा विशेषज्ञ/अभिकरण अपनी अधिकारिता में स्थित केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या अनुमोदित मध्यवर्तियों के समस्त या किसी शाखा/कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है।
  - (2) तथापि, निबंधन महानिरीक्षक उप-नियम (1) में उल्लिखित नियमित निरीक्षणों के अतिरिक्त किसी शिकायत की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से विभाग के किसी पदाधिकारी को केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या अनुमोदित मध्यवर्ती की किसी शाखा या कार्यालय का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
  - (3) महालेखाकार, बिहार द्वारा भी केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा की गयी प्राप्तियों एवं प्रेषण की संपरीक्षा की जा सकती है।
33. केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा राज्य में अनुमोदित मध्यवर्ती की समस्त या किन्हीं शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण और संपरीक्षा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी समय सारणी के अनुसार की जायेगी।
34. ऐसे निरीक्षण के दौरान निरीक्षण कर्ता अधिकारी अथवा विशेषज्ञ/अभिकरण निरीक्षित शाखा/कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी से किसी भी अवधि से संबंधित न्यायालय फीस के संग्रह एवं प्रेषण विषय सूचना किसी इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल अभिलेख की सॉफ्ट अथवा हार्ड कॉपी पर उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षा कर सकता है और संबंधित केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण अथवा अनुमोदित मध्यवर्ती ऐसी सूचना को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायेगा।
35. निरीक्षणकर्ता अधिकारी तथा तकनीकी एवं संपरीक्षा/अभिकरण चूकों, उल्लंघनों विलंबों या अनियमितताओं यदि कोई है आदि का उल्लेख करते हुये सुझाव एवं अनुशंसा के साथ निरीक्षण रिपोर्ट निबंधन महानिरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।
36. निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निबंधन महानिरीक्षक संबंधित प्रकरण में समुचित कार्रवाई करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकार से अर्थदण्ड के अधिरोपण और केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या संग्रह केंद्र के रूप में प्राधिकृत अभिकरण की नियुक्ति समाप्त करने (यदि परिस्थितियों से ऐसा आवश्यक हो) की अनुशंसा कर सकता है।

यदि निबंधन महानिरीक्षक को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति प्राधिकार के रूप में भी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो तो वह उस है सियत से समुचित कार्यवाही करेगा।

37. केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या संग्रह केंद्र के रूप में प्राधिकृत अभिकरण की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार निरीक्षण/तकनीकी संपरीक्षा रिपोर्ट और निबंधन महानिरीक्षक की अनुशंसाओं के आधार पर कोई समुचित कार्यवाही जैसा वह उचित समझे, कर सकता है।

#### अध्याय-9

#### चूकों और उल्लंघनों के लिए दण्ड

38. यदि केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण नियम 19 के उप नियम (1) में यथा निर्धारित काल अवधि में न्यायालय फीस के रूप में संग्रहीत की गई धनराशि के राज्य सरकार के समुचित लेखाशीर्षक में प्रेषित करने में विफल रहता है, तो केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण संग्रहीत न्यायालय फीस की धनराशि के अतिरिक्त विलंब के लिए अर्थदण्ड एकरारनामा के शर्तों के अनुसार अधिरोपित होगा।

39. यदि केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या इसके प्राधिकृत संग्रह केंद्रों में से किसी के द्वारा किये गये कार्य में चूक, अनियमितता अथवा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप सरकार को राजस्व क्षति हुई हो, तो केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण राजस्व की क्षति की धनराशि के साथ डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज एवं सरकार को हुई राजस्व क्षति की धनराशि के दो गुने से अनाधिक धनराशि के अर्थदण्ड के साथ प्रतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा।

40. यदि केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण इन नियमों के अंतर्गत सरकार को देय धनराशि और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड नहीं देता है तो इसकी वसूली बकाया कमीशन की राशि में से की जायेगी।

#### अध्याय-10

#### प्रबंध सूचना प्रणाली/निर्णय समर्थन प्रणाली

41. (1) केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण निबंधन महानिरीक्षक तथा महानिबंधक उच्च न्यायालय एवं अन्य ऐसे सभी अधिकारियों को, जिन्हें उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करायेगा, जिससे कि ई-कोर्ट फीस प्रणाली में वांछित प्रतिवेदन को ऑनलाइन प्राप्त किया जा सके।
- (2) केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण निम्नलिखित सूचना रिपोर्ट्स को निबंधन महानिरीक्षक तथा महानिबंधक उच्च न्यायालय और किसी या अन्य ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि वो निर्दिष्ट करें, सूचना उपलब्ध करायेगा, जिसमें निम्न प्रतिवेदन सम्मिलित हैं: —
  - (i) **सम्परीक्षा अन्वेषण प्रतिवेदन:** — किसी विनिर्दिष्ट दिवस अथवा अवधि से संबंधित केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण एवं प्राधिकृत संग्रह केंद्रों की संग्रह शाखाओं कार्यालयों के उपयोक्ताओं द्वारा निष्पादित प्रणाली पर समस्त कार्यवलयों का पता लगाना।
  - (ii) **सरकार संदेय प्रतिवेदन:** — किसी विनिर्दिष्ट दिवस अथवा अवधि को प्राधिकृत संग्रह केन्टवार (केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण शाखाओं सहित) संपूर्ण संग्रह प्रतिवेदन।
  - (iii) **अतिरिक्त न्यायालय फीस प्रमाण पत्र प्रतिवेदन:** — किसी विनिर्दिष्ट दिवस अथवा अवधि से संबंधित केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत केंद्रों की समस्त या किसी संग्रह शाखा/कार्यालय के लिए।
  - (iv) **लाकड ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्र प्रतिवेदन:** — किसी विनिर्दिष्ट दिवस या अवधि से संबंधित समस्त न्यायालयों में से किसी के संबंध में।
  - (v) **प्रेषण प्रतिवेदन:** — किसी विनिर्दिष्ट दिवस या अवधि के संबंध में केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा कृत प्रेषणों का जिलेवार ब्यौरा।
  - (vi) **निरस्त ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों की प्रतिवेदन:** — किसी विशिष्ट दिवस या अवधि से संबंधित प्रतिवेदन।
  - (vii) **प्रमाण पत्र उत्पादन प्रतिवेदन:** — किसी विनिर्दिष्ट दिवस या अवधि के संबंध में केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रह केंद्रों की कोई-समस्त संग्रह शाखाओं/कार्यालयों के लिए उत्पादित ई-कोर्ट फीस प्रमाण पत्रों का प्रतिवेदन।
  - (viii) **वार्षिक न्यायालय फीस संग्रह प्रतिवेदन:** — केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रह केंद्रों की कोई-समस्त संग्रह शाखाओं/कार्यालयों द्वारा संग्रहीत न्यायालय फीस का वार्षिक प्रतिवेदन।



- (ix) न्यायालय फीस सदृश संग्रह प्रतिवेदन: — केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रह केंद्रों की कोई-समस्त संग्रह शाखाओं/कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष के दस्तावेज मासिक न्यायालय फीस संग्रहों की श्रेणी प्रदर्शित होगी।
- (x) मासिक न्यायालय फीस संग्रह का प्रतिवेदन: — केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रह केंद्रों की कोई-समस्त संग्रह शाखाओं/कार्यालयों के लिए किसी कैलेण्डर वर्ष की मासिक फीस संग्रह का प्रतिवेदन।
- (xi) निबंधन महानिरीक्षक द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित कोई अन्य प्रतिवेदन या सूचना।

#### अध्याय-11 कोषागार की भूमिका

42. कोषागार पदाधिकारी, राजकीय व्यवसाय शाखा से प्राप्त लेखासूची से केंद्रीय अभिलेख-अनुरक्षण अभिकरण द्वारा नियम 19 में निर्दिष्ट सरकारी खाता में न्यायालय फीस के दैनिक प्रेषणों के ब्यूरो का सत्यापन करेगा।

#### अध्याय-12 शक्तियों का प्रत्यायोजन

43. नियुक्ति प्राधिकार लिखित आदेश द्वारा सभी अथवा किसी शक्ति एवं/अथवा कार्य का प्रत्यायोजन विभाग के किसी पदाधिकारी को कर सकता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**आमिर सुबहानी,**  
सरकार के प्रधान सचिव।

23 मार्च 2018

सं० 10/मु. नियमावली-05/2018-1060—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
**आमिर सुबहानी,**  
सरकार के प्रधान सचिव।

#### *The 23<sup>rd</sup> March 2018*

NO. 10/Mu. Nimawali-05/2018-1060— In exercise of the power conferred Section 27 and Section 34 of the Court Fees Act, 1870 (Act No.-VII of 1870), the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate the payment of Court Fee through e-court fee in the courts & the offices of the State: -

#### **THE BIHAR E-COURT FEES (IMPLEMENTATION BY AGENCY) RULES, 2018 CHAPTER-1**

**1. Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Bihar E-Court Fees (Implementation by Agency) Rules, 2018.

- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force with effect from the date of notification.
- (4) This rule will be in force in pursuance to Notification No.-2039 Dated 02.05.2017 & Agreement related to that.

**2. Definitions.-** (1) *In these rules unless there is any thing repugnant in the subject or context: -*

- (i) “Act” means the Court Fees Act, 1870 (Act No.-VII of 1870), as amended from time to time in its application to Bihar;
- (ii) “Agreement” means the agreement executed between the Appointing Authority and the Central Record-keeping Agency describing the terms and Conditions of appointment of the Central Record-keeping Agency;
- (iii) “Appointing authority” means the Government or the The Inspector General of Registration , authorized by the Government in this behalf by notification in the Gazette for all or any specific purpose under these rules;
- (iv) “Approved Intermediaries” means the Central Record- keeping Agency and the Authorized Collection Centers including all its offices and branches as appointed with the prior approval of the Appointing Authority to act as an intermediary between the Government and the Court Fees payer for collection of Court Fees under these rules;
- (v) “Authorized Collection Centre” means an agent appointed by the Central Record-keeping Agency, with the prior approval of the Appointing Authority, to act as an intermediary between the Central Record-keeping Agency and the Court Fees payer for collection of Court Fees;
- (vi) “Central Record-keeping Agency” means an agency appointed by the Appointing Authority for computerization of Court Fees Administration System in the State or at such places as the Appointing Authority may determine from time to time;
- (vii) “Department” means the Prohibition, Excise and Registration Department, Government of Bihar;
- (viii) “Form” means a Form prescribed by the Appointing Authority/ Registrar General of the High Court from time to time;
- (ix) “Government” means the State Government of Bihar;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings respectively assigned to them in the Court Fees Act, 1870 (as amended from time to time in application to Bihar).

## **CHAPTER-2**

### **APPOINTMENT OF CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY**

3. Any public Financial Institution, Indian Scheduled Bank, a Company engaged in providing depository services appointed by Central Government, accompany recognized by the Government either in dividedly or in consortium may be eligible or appointment as Central Record-keeping Agency.

4. The Appointing Authority shall select and appoint by notification a suitable agency to function as Central Record-keeping Agency for the State to implement the Computerization of Court Fees Administration System in specified courts of the State as declared by the Appointing Authority from time to time, in the order as mentioned below: -

- (1) On the basis of recommendations, if any, of the Central Government regarding appointment of Central Record-keeping Agency, issued from time to time;
- (2) By inviting technical and financial bids through a duly constituted expert Selection Committee.

5. The term of Central Record-keeping Agency appointed under these rules shall be five years.
6. (1) The appointment of the Central Record-keeping Agency shall be on contract basis and the Agency shall enter into an Agreement with the Appointing Authority.
- (2) The Central Record-keeping Agency shall along with the agreement referred to in sub-rule (1) execute an Under taking, Indemnity Bond and bank guarantee in favor of the Appointing Authority in the manner determined by the Appointing Authority from time to time.
7. (1) The appointment of the Central Record-keeping Agency may be terminated earlier than the agreed term of appointment, on the ground of any breach of obligation, terms of agreement, the provisions of these rules or the Act, financial irregularity or for any other sufficient reason which shall be recorded in writing.
- (2) The decision to terminate the appointment will be taken-
  - (i) after the Central Record-keeping Agency has been given a show-cause notice specifying the details of grounds under sub-rule (1);
  - (ii) after the Central Record-keeping Agency has been given a reasonable opportunity of being heard;
  - (iii) after consideration of the explanation offered by the Central Record-keeping Agency; and
  - (iv) in case of breach of obligation, if the Central Record-keeping Agency fails to cure the breach within the period specified in the show-cause notice.
- (3) If the ground, on which the Appointing Authority has decided to terminate the appointment, is such that it has also caused loss of revenue to the State, the Central Record-keeping Agency shall be bound to pay the entire amount of revenue loss, in addition to such amount of penalty as may be imposed by the Appointing Authority.
- (4) On termination of appointment under this Rule, the Central Record-keeping Agency shall transfer all the data generated during the period of appointment to the Government. After the termination of the appointment, the Central Record-keeping Agency, shall not use or cause to be used the data generated during the period of appointment for its business or any other purpose.
8. (1) The application for renewal of appointment of the Central Record-keeping Agency will be made to the Appointing Authority at least three months before the expiry of the running term of appointment.
- (2) The Appointing Authority may, before taking decision on the application for renewal of the appointment of the Central Record-keeping Agency, call for any information or record from the Department or the Central Record keeping Agency or the Authorized Collection Centers or any other person or body.
- (3) The Appointing Authority, on being satisfied about the suitability of renewal, may renew the appointment.
- (4) If the Appointing Authority decide store new the appointment, afresh agreement referred in sub-rule(1) of Rule (6) and Undertaking and Indemnity Bond referred to in sub-rule (2) of Rules (6), will be executed with suitable amendments, if any.

- (5) The Appointing Authority shall have power to refuse the renewal of the term of appointment for reasons to be recorded in writing.

### CHAPTER-3

#### DUTIES OF THE CENTRAL RECORD-KEEPING AGENCY

9. (1) The Central Record-keeping Agency shall be responsible for-
- (i) creating need based infrastructure, hardware and software in the designated places in consultation with the Appointing Authority and its connectivity with its main server;
  - (ii) creating need based hardware and software in designated Courts, and at authorized collection centers (the point of contact for payment of Court Fees) in the identified cities/places;
  - (iii) providing suitable and adequate training for operation and the use of the system to the personnel of Department/ Courts as may be specified from time to time by the Appointing Authority;
  - (iv) facilitating in selection of Authorized Collection Centers for collection of Court Fees and issuing of e-Court Fees certificates;
  - (v) coordinating between the central server of Central Record-keeping Agency, Authorized Collection Centers, offices of Courts, supervisory and controlling officers/court sand any other office or places as may be specified by the Appointing Authority;
  - (vi) collecting Court Fees in accordance with these Rules and remitting it in the proper Head of Account of the State as directed from time to time by the Appointing Authority;
  - (vii) Developing and designing various reports as required under these Rules and as directed by the Patna High Court Patna and the Appointing Authority from time to time;
  - (viii) It shall be duty of the Central Record-keeping Agency to develop there quired inter faces as may be mutually agreed upon between Appointing Authority, Central Record Keeping Agency and the Court.
  - (ix) To follow the provisions made for payment of fee through "in payment" by Patna High Court in the Court Fee Rules, High Court Rules, Civil Court Rules and Criminal Court Rules of the High Court Judicature at Patna and in respect of Welfare Fund Stamp.
- (2) The Central Record-keeping Agency shall not provide, transfer or share without the written permission of the Appointing Authority any hardware, software or any other technology or details in respect of the E-Court Fees project under taken by it in the State to any body other than the duly appointed Authorized Collection Centers.
10. (1) The Central Record-keeping Agency shall been titled to such Commission on the amount of E-Court Fees collected as per the agreement.
- (2) The commission payable to the Central Record-keeping Agency shall be subject to the condition specified in Rule-19.

11. (1) The Central Record-keeping Agency shall have to design and use such software in such a manner that the following minimum details are shown on the E-Court Fees certificate: -

- (i) Distinguished Unique Identification number of the Certificate so that it is not repeated on any other certificate during the lifetime of the E-Court Fees system;
- (ii) date and time of issue;
- (iii) amount of Court Fees paid through the certificate in words and figures;
- (iv) in case of E-Court Fees certificate above ninety nine rupees, name of the litigant;
- (v) location code of the issuing branch or the Approved Intermediary; and
- (vi) any other distinguishing mark on the certificate e.g. bar code etc., if any,

(2) The software to be used by the Central Record-keeping Agency shall also provide: -

- (i) facility to Courts/ Designated Officials to lock the E-Court Fees certificate used in a document;
- (ii) facility to cancel the spoiled, unused or not required E-Court Fees certificate;
- (iii) necessary user ID and passwords to be used by the designated officials of the Court to search, access and view any E-Court Fees certificate and to access Management Information System. The Central Record-keeping Agency shall provide these passwords to the concerned officials or the Courts as directed by the Appointing Authority or Registrar General of the High Court;
- (iv) availability of details of the issued E-Court Fees certificate on the E-Court Fees Server maintained by the Central Record-keeping Agency; and
- (v) availability of the different transaction details and reports relating to E-Court Fees on the website of the Central Record-keeping Agency which will be accessible to the officers mentioned in sub-rule(2)(c).

#### **CHAPTER-4**

#### **AUTHORIZED COLLECTION CENTERS**

12. The Central Record-keeping Agency may appoint agent(s), here in after called Authorized Collection Centers, with the prior approval of the Appointing Authority, to act as an in term diary between the Central Record-keeping Agency and the Court Fees payer for collection of Court Fees. The service charges, commission, or fee etc. payable to Authorized Collection Centers shall be paid by the Central Record-keeping Agency at their own level as mutually agreed between them.

13. (1) Any scheduled bank, any financial institution, an undertaking controlled by the Reserve Bank of India or the Financial Institution, Undertaking controlled by the Government, or a Post Office will be eligible for appointment as Authorized Collection Centre, subject to prior approval of the Appointing Authority under rule 12.

(2) An individual may be appointed to act as Authorized Collection Centre on terms and conditions prescribed by the Appointing Authority in consultation with the Central Record-keeping Agency.

- (3) An individual may also purchase E-Court Fees certificate online after registering on the website of the Central Record-keeping Agency by one self or may prescribe it through an authorized agent.

14. All the offices/branches of the Central Record-keeping Agency in specified places of the State, as declared by Appointing Authority from time to time, may collect the payment of Court Fees for which separate approval from the Appointing Authority under Rule 12 will not be required.

15. All such Approved Intermediaries shall be equipped with the required computers, printers, internet connectivity, and other related infrastructure, which is necessary to implement the E-Court Fees system as specified by the Central Record-keeping Agency from time to time.

16. The cost of providing equipment and infrastructure referred to in Rule 15 will be borne by the concerned approved intermediaries.

17. State may specify Courts/ places to establish counter for issue of E-Court Certificate.

18. The Appointing Authority may at any time, for reasons to be recorded in writing, advise the Central Record-keeping Agency to terminate the agency of any Authorized Collection Centre and the Central Record-keeping Agency shall on such advice terminate the agency of such Authorized Collection Centre.

## **CHAPTER-5**

### **REMITTANCE OF THE COURT FEES TO GOVERNMENT ACCOUNT**

19. (1) The Central Record-keeping Agency shall reconcile and deposit the consolidated amount of Court Fees collected by its offices/branches and by its Authorized Collection Centers in the proper head of account of Court Fees, as may be notified from time to time by the Government, not later than the closure of business hours of next working day from the date of such collection of Court Fees or within such period as may be prescribed to in the Agreement, which shall not be more than two working days.
- (2) The method of remittance of the Amount of Court Fees by the Central Record keeping Agency to the proper head of the State shall be through Electronic Clearing System (ECS), Real Time Gross Settlement (RTGS), National Electronic Fund Transfer (NEFT), Challan or as directed in writing by the Appointing Authority from time to time.
- (3) The deposit referred in sub-rule(1) shall be transferred to the Government account under specified head of account by means of depositing through challan in the banks authorised to carryon Government transactions. The Government Treasury or Authorized Banks and the Central Record-Keeping Agency shall maintain the daily account of such deposits in a Register which shall be in such form as may be determined from time to time by the Appointing Authority.
- (4) The Central Record-keeping Agency shall be paid commission on the basis of the consolidated receipt statement submitted by it either on a monthly or bi-monthly basis as may be determined from time to time by the Government or in accordance with the Agreement. The commission shall be paid under this sub-rule after deducting Income Tax at source. The Central Record-Keeping Agency shall be liable to pay other taxes payable under Central or State Act.

## CHAPTER-6

### PROCEDURE FOR ISSUE OF E-COURT FEES CERTIFICATE

20. A person desiring to pay Court Fees shall make an application in the prescribed Form to any of the branch of the Central Record-keeping Agency or Approved Intermediaries with the requisite details for getting the E-Court Fees certificate.

21. Payment of the amount of Court Fees shall be made by Cash or Pay Order or Cheque or Bank Draft or Electronic Clearing System or Real Time Gross Settlement or any other mode of transfer of funds, as may be directed by the Appointing Authority.

22. (1) The Authorized official of approved Intermediary shall issue the E-Court Fees certificate under rule 22.

(2) The Approved Intermediary issuing the E-Court Fees certificate shall keep a daily account of issued E-Court Fees certificates in a Register to be maintained and take signature of purchaser or the authorized person; as the case may be, on the relevant column of the Register.

23. The Approved Intermediary shall ensure that the person assigned the duty of issuing E-Court Fees certificate is a duly authorized representative of the Agency or Institution and has suitable credentials.

24. The printing of E-Court Fees certificate shall be done by non-washable permanent black ink on a durable paper or in a manner determined by the Appointing Authority.

25. The details of issued E-Court Fees certificate shall be made available on the E-Court Fees website maintained by the Central Record-keeping Agency and shall be accessible to any person authorized by the Appointing Authority in this behalf including the Courts holding a valid User ID and password which shall be provided by the Central Record-keeping Agency.

26. Any person who holds E-Court Fees certificate and is required to pay an additional amount of Court Fees; may make an application in the Form prescribed with payment of such amount of additional Court Fees to the Approved Intermediary.

27. (1) The Approved Intermediary shall issue E-Court Fees certificate for such additional Court Fees on separate sheet of paper in the manner prescribed in rules 21 to 25.

(2) Judicial stamp may be used together with the E-Court Fees certificates to pay the Court Fees chargeable on a document under the Act.

28. (1) E-Court fees Certificate used in a document shall not be used in any other document.

(2) A document not in compliance with sub-rule (1) shall be deemed to be unstamped and shall be dealt with under the provisions of the Act.

29. A distinguished unique identification number of the E-Court Fees certificate shall be written or printed at the top of the document.

30. Verification and locking the details of E-Court Fees certificate.—Courts, after making the enquiry envisaged by the Act, shall verify the correctness and authenticity of the E-Court fees certificate used in the document by accessing the relevant website of the Central Record-keeping Agency, to verify its authenticity either by using unique identification number or with the help of a bar code scanner. After such verification, the Courts shall lock the E-Court Fees Certificate by using user ID Code and password provided by the Central Record-keeping Agency to prevent use of such certificate.

The concerned officer shall not disclose the user ID and password provided by the central Record-keeping Agency, and if the wrong and unauthorized use there of results in a loss to the State Government, the concerned officer shall be held responsible for the same.

## **CHAPTER-7**

### **REFUND OF E-COURT FEES**

31. (1) The procedure for refund prescribed under the Court Fees Act, 1870, Bihar stamp rules, 1954 and rules made under court fee Act, 1870 by Bihar Government shall apply mutatis mutandis with such modifications as are necessary.
- (2) An application for refund of 'spoiled' or 'misused' or 'not required' E-Court Fees certificate shall be made in the Form prescribed along with the E-Court Fees certificate to the Collector within whose jurisdiction the E-court fees certificate is required to be locked by the Court for use.
- (3) On verification from the Central Record-keeping Agency, related court's registry and related treasury the Collector shall cancel and lock the verified E-Court Fees certificate and endorse "CANCELLED" on the original E-Court Fees certificate with his signature and seal.
- (4) The Collector shall maintain a record of such cancelled E-Court Fees certificate in his office.
- (5) There is any fault in the e-Court fee certificate can be rectified till the time related amount is not transferred in the account of the Government and record relating to this shall be maintained by the Central Record-keeping Agency. Also, it shall be included in the MIS report of that day.
- (6) On being satisfied from the verification reports under rule-3, if it is established that the applicant has deposited the amount of stamp duty as indicated in the application and the amount has not been utilized for registration, the amount shall be refunded after deducting 10% of the deposited amount subject to a minimum of Rs. 200/- (Rupees two hundred) and a maximum of Rs. 5000/- (Rupees five thousand).

## **CHAPTER-8**

### **INSPECTIONS, AUDIT AND APPRAISAL OF THE PERFORMANCE OF THE SYSTEM**

32. (1) Officers authorized to inspect, any supervisory officer of the Department or any private or public sector technical cum audit expert/agency duly authorized by the Appointing Authority or by the Inspector General of Registration in this behalf may inspect all or any of the branches/offices of the Central Record-keeping Agency and Approved Intermediaries located within its jurisdiction.
  - (2) The Inspector General of Registration may, however, at any time on receipt of a complaint or suo-motu, direct any official of the Department to inspect any branch or office of the Central Record-keeping Agency or Approved Intermediaries and to submit a report, besides the regular inspections mentioned in sub-rule(1).
  - (3) The Accountant General, Bihar may also make audit of the receipts and remittances made by the Central Record-keeping Agency.
33. All or any of the branches/ offices of the Central Record-keeping Agency and Approved Intermediaries in the State will be inspected and audited as per the schedule provided by the appointing authority.



34. During such inspection the Inspecting Officer or the expert/agency may require the Officer In-charge of the inspected branch/office to provide any information on soft and/or hard copy of any electronic or digital record related to the collection and remittance of Court Fees relating to any period of same and the concerned Central Record-keeping Agency or Approved Intermediary shall provide such information on priority basis.

35. The Inspecting Officer and the technical-cum-audit expert/agency shall submit inspection report mentioning the omissions, violations, delay sorer regularities, if any, and give suggestion sand recommendations to the The Inspector General of Registration .

36. The The Inspector General of Registration on receipt of inspection report shall take appropriate action in the matter and may (if so warranted by the circumstances) make recommendation to the Appointing Authority, including imposition of penalty and/ or termination of appointment of Central Record-keeping Agency or the agency Authorized as Collection Centre. If the The Inspector General of Registration is also authorized by the Government to function as Appointing Authority, he will take appropriate action in that capacity.

37. The Appointing Authority may, after giving a reasonable opportunity of being heard to the Central Record-keeping Agency or the Agency authorized as Collection Centre, take any appropriate action as it deems fit on the basis of the inspection/technical audit report and the recommendations of the The Inspector General of Registration .

## **CHAPTER-9**

### **PENALTY FOR OMISSIONS AND VIOLATIONS**

38. In case the Central Record-Keeping Agency fails to remit the amount of collected Court Fees in proper Account Head of the State within the period stipulated in sub-rule(1) of rule 19, the Central Record-Keeping agency shall be liable to pay penalty for the delay, be sides the collected amount of Court Fees as per the terms of the agreement.

39. If any act, omission, irregularity or violation on the part of the Central Record-keeping Agency or any of its Authorized Collection Centers has resulted in loss of revenue to the Government, the Central Record-keeping Agency shall indemnify such amount of loss of revenue along with interest calculated at the rate of one and half percent permen-sum and penalty not exceeding twice the lossof revenue to the Government.

40. In case, the Central Record-keeping Agency does not to pay the amount due to the Government and the penalty imposed by the Appointing Authority under these Rules, such amount may be recovered from the arrear of the commission.

## **CHAPTER-10**

### **MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM/DECISION SUPPORT SYSTEM**

41. (1) The Central Record-keeping Agency shall provide Login ID and password to the The Inspector General of Registration and the Registrar General of the High Court and to any or all such officers as they may direct in this regard, for online access of the required information report in the E-Court Fees system.
- (2) The Central Record-keeping Agency shall furnish such in formation including the following information reports to the The Inspector General of Registration and the Registrar General of the High Court and to any or all such other officers as they may direct: -

- (i) *Audittrail report*-Tracking of all system based actions performed by users of collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers pertaining to any specified day or period;
- (ii) *Government payable reports.*— Authorized Collection Center-wise (including collection branches of the Central Record-keeping Agency) total collection report of any specified day or period;
- (iii) *Additional Court Fees certificate reports.*—For all or any of the collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and Authorized Collection Centers pertaining to any specified day or period;
- (iv) *Locked E-Court Fees certificate reports.*-Relating to all or any of the Courts pertaining to any specified day or period;
- (v) *Remittance reports.*— A district-wise details of the remittances made by the Central Record-keeping Agency into the Government Account pertaining to any specified day or period;
- (vi) *Report of cancelled E-Court Fees certificates*- Report pertaining to specified day or period;
- (vii) *Certificate Generation reports.*— Reports of E-Court Fees certificates generated for any/ all collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers pertaining to any specified day or period;
- (viii) *Yearly Court Fees Collection reports.* – Yearly report of Court Fees collected by any/all of the collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers;
- (ix) *Court Fees Type Collection report.* – Showing category of document-wise monthly Court Fees collections of any calendar year for any/all collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers;
- (x) *Court Fees monthly collection report.* – Court Fees monthly collection report of any calendar year for Any/all of the collecting branches/offices of the Central Record-keeping Agency and the Authorized Collection Centers; and
- (xi) Any other report or information as may be required by The Inspector General of Registration from time to time.

## CHAPTER-11 ROLE OF TREASURY

42. The Treasury Officer shall verify from the account scroll received from the branch of the bank carrying on the work of Government Business Branch, the details of the daily remittances of Court Fees made by the Central Record-keeping Agency into the Government Account referred to in rule 19.

---

**CHAPTER-12**  
**DELEGATION OF POWERS**

43. The Appointing Authority by making an order in writing may delegate all or any of its powers and/or functions to the officers(s) of the Department.

By the order of the Governor of Bihar,

**AMIR SUBHANI,**

*Principal Secretary to Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 269-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>